

शिक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया का बदलता परिदृश्य : भारत के संदर्भ में

डॉ. संजय कुमार गुप्ता

सेवा निवृत्त व्याख्याता

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कुमारबाग, पश्चिम चम्पारण, बिहार

Email: ksgupta016@gmail.com



Received 01 September 2026

Accepted 05 September 2026

Published 10 September 2026

Corresponding Author:

डॉ. संजय कुमार गुप्ता

Email: ksgupta016@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.64880/pcjaict.v1i5.05>

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

Copyright: © 2026 The Author(s).



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

OPEN ACCESS

प्रस्तावना:-

व्यक्ति एवं समाज के सर्वांगीण विकास के रूप में शिक्षा प्रमुख साधन है और मूल्यांकन इसकी गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता को जानने का व्यवस्थित एवं महत्वपूर्ण माध्यम। मूल्यांकन में यह जानने का प्रयास किया जाता है की शिक्षार्थी ने क्या सीखा कितना सीखा और वह सीखे गए ज्ञान एवं कौशलों का प्रयोग

सारांश :

मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है जो न केवल शिक्षार्थियों के उपलब्धि का आकलन करती है बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं पाठ्यचर्या दोनों को दिशा दिखाती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप में समय के साथ आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था अंतर्गत मूल्यांकन मुख्यतः शिक्षार्थी के तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, दैनिक व्यवहार, व्यावहारिक दक्षता, अनुशासन, नैतिक आचरण, व्यक्तिगत क्षमताओं के निरंतर अवलोकन पर आधारित था। औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था में निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समान प्रश्न पत्र, अंक आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली एवं प्रमाण पत्र आधारित केंद्रीय कृत मूल्यांकन व्यवस्था को तवज्जो दिया गया। जो प्रशासनिक दृष्टि से राष्ट्र स्तर पर शिक्षा के मानकीकरण को तो संभव कर पाया, परंतु मूल्यांकन धीरे-धीरे स्मृति पुनर्उत्पाद, व्यक्तिगत स्पर्धात्मक एवं परीक्षा केंद्रित बन गया। स्वतंत्रता के उपरांत विभिन्न आयोगों के सिफारिश के आधार पर मूल्यांकन को अधिक व्यापक बल केंद्रित विकासोन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक पक्ष के साथ-साथ सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, व्यावसायिक पक्षों के विकास को भी सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया गया। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन को सिखाने में सुधार करने वाली सतत एवं रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया यह परिवर्तन भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, बाल केंद्रित, व्यावहारिक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख बिंदु:- प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विद्यालय आधारित मूल्यांकन

विभिन्न व्यावहारिक परिस्थितियों में किस अनुरूप करता है। वर्तमान शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालय आधारित मूल्यांकन शिक्षार्थी की वास्तविक परिस्थितियों में सीखने की प्रगति को समझने का अवसर प्रदान करती है। इसमें परियोजना कार्य, गतिविधि आधारित अधिगम, मौखिक प्रस्तुति वाद-विवाद, परिचर्चा आदि के आधार पर शिक्षार्थी के स्व-मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन एवं शिक्षक के सतत अवलोकन को सम्मिलित किया जाता है। अतः वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था परीक्षा केंद्रिता से दक्षता, समग्र विकास, व्यक्तिगत क्षमता एवं गुणवत्तापूर्ण अधिगम की ओर संक्रमण को दर्शाता है। भविष्य की मूल्यांकन प्रणाली का लक्ष्य यह निर्धारित करना नहीं होना चाहिए कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा बल्कि यह होना चाहिए कि शिक्षार्थी अपने सीखे ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में किस सार्थकता के साथ प्रयोग कर पाने में सफल है

उद्देश्य:-

इस आलेख का उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन की ऐतिहासिक यात्रा में इसके बदलते स्वरूप और भूमिका का विश्लेषण करना है। यहाँ प्राचीन, औपनिवेशिक एवं आधुनिक मूल्यांकन पद्धतियों की विशेषताओं, सीमाओं एवं प्रमुख प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की आवश्यकता को स्पष्ट करेगा। साथ ही मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, सृजनात्मकता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं भावनात्मक विकास को समझने के उपायों पर चर्चा करेगा। इसका प्रमुख लक्ष्य मूल्यांकन को सिखाने में सहायक, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की संभावनाओं और चुनौतियों को रेखांकित करना है।

शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया मुख्यतः तीन आधारभूत स्तंभों-पाठ्यचर्या (Curriculum), शिक्षणशास्त्र अथवा शिक्षण विधि (Pedagogy) तथा मूल्यांकन एवं आकलन (Assessment and Evaluation)-पर आधारित होती है। ये तीनों तत्व परस्पर संबंधित एवं एक-दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता इन तीनों के संतुलित समन्वय पर निर्भर करती है। पाठ्यचर्या यह निर्धारित करती है कि विद्यार्थियों को क्या सीखना है, शिक्षणशास्त्र यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें किस प्रकार सिखाया जाए, जबकि मूल्यांकन यह स्पष्ट करता है कि विद्यार्थियों ने वास्तव में क्या तथा किस स्तर तक सीखा है। प्रारंभिक शिक्षा दर्शन में मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का केवल अंतिम चरण नहीं माना जाता था, बल्कि इसे वह केंद्रीय तत्व समझा जाता था जो पाठ्यचर्या एवं शिक्षण दोनों को दिशा एवं गति प्रदान करता था तथा अनेक परिस्थितियों में उन्हें नियंत्रित भी करता था।

भारत की शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय तक मूल्यांकन का स्वरूप परीक्षा-केंद्रित रहा, जिसमें वार्षिक परीक्षा, अंक एवं उत्तीर्णता को शिक्षा की सफलता का प्रमुख आधार माना जाता था। इस व्यवस्था ने रटने की प्रवृत्ति, परीक्षा-भय, प्रतिस्पर्धात्मक तनाव तथा स्मृति-आधारित अधिगम को बढ़ावा दिया। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान क्षमता तथा जीवन कौशलों के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका। धीरे-धीरे यह अनुभव किया गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं हो सकती। वास्तविक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह है जो प्रत्येक बालक की सीखने की गति, रुचि, क्षमता एवं अभिव्यक्ति के अनुरूप हो। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया भी बहुआयामी, बाल-अनुकूल एवं विकासोन्मुख होनी चाहिए।

प्राचीन भारतीय गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सांस्कृतिक, नैतिक, व्यावसायिक तथा आध्यात्मिक विकास करना था। गुरु और शिष्य के मध्य घनिष्ठ संबंध शिक्षा का आधार था। इस काल में मूल्यांकन की कोई औपचारिक लिखित परीक्षा प्रणाली नहीं थी। विद्यार्थियों का आकलन उनके दैनिक व्यवहार, अनुशासन, तर्क क्षमता, स्मरण शक्ति, सेवा भावना, नैतिक आचरण तथा व्यवहारिक कौशलों के आधार पर किया जाता था। गुरु विद्यार्थियों का निरंतर अवलोकन करते थे तथा उसी के आधार पर उनकी प्रगति की दिशा निर्धारित करते थे।

गुरुकुल व्यवस्था में व्यक्तिगत क्षमता (Individual Competence) को विशेष महत्त्व दिया जाता था। प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, योग्यता तथा सीखने की गति भिन्न मानी जाती थी। इसी कारण शिक्षा एवं मूल्यांकन दोनों व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप होते थे। उदाहरणस्वरूप कोई विद्यार्थी शास्त्रार्थ

में कुशल होता था, कोई युद्धकला में, कोई नृत्य एवं संगीत में, तो कोई आध्यात्मिक चिंतन आदि में। गुरु प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानकर उसी दिशा में उसका मार्गदर्शन करते थे। इस प्रकार मूल्यांकन का उद्देश्य तुलना करना नहीं, बल्कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत प्रगति एवं आत्मविकास सुनिश्चित करना था।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन ब्रिटिश काल में आया। थॉमस बैबिंगटन मैकॉले की शिक्षा नीति के प्रभाव से भारतीय शिक्षा प्रणाली में औपचारिक विद्यालय, निश्चित पाठ्यचर्या, निर्धारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, कक्षा प्रणाली एवं अंक आधारित लिखित परीक्षा व्यवस्था का विकास हुआ जो ब्रिटिश शासन के उद्देश्यों के अनुकूल था, अर्थात् ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करना जो प्रशासनिक कार्यों में सहायक हो सकें। परिणामस्वरूप मूल्यांकन प्रणाली अधिक केंद्रीकृत, मानकीकृत एवं परीक्षा-केंद्रित बन गई।

इस काल में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमता एवं व्यवहारिक दक्षताओं की अपेक्षा लिखित परीक्षा, अंक आधारित एवं प्रमाणपत्रों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। समान प्रश्नपत्र, निश्चित समय तथा अंक प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाने लगा। इससे शिक्षा में प्रशासनिक नियंत्रण एवं चयन प्रक्रिया सरल हुई, परंतु शिक्षा धीरे-धीरे स्मृति-आधारित अधिगम तथा रटने की प्रवृत्ति तक सीमित हो गई। शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों का ध्यान वास्तविक अधिगम के बजाय परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर केंद्रित होने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह अनुभव किया गया कि ऐसी परीक्षा प्रणाली विद्यार्थियों के वास्तविक अधिगम, सृजनात्मकता एवं जीवन कौशलों का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाती। इसी कारण विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में मूल्यांकन सुधार पर विशेष बल दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में यह अनुभव किया गया कि ब्रिटिशकालीन परीक्षा प्रणाली भारतीय समाज एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि रचनात्मक, जागरूक, संवेदनशील एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए। इसी कारण विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने मूल्यांकन सुधार पर अत्यधिक बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने परीक्षा सुधार एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया। इसके पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE) की अवधारणा प्रस्तुत की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ सामाजिक, भावनात्मक एवं शारीरिक विकास का समग्र मूल्यांकन करना था। इसमें केवल वार्षिक परीक्षा ही नहीं, बल्कि परियोजना कार्य, कक्षा सहभागिता, मौखिक प्रस्तुति तथा सहशैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता एवं परिचर्चा को भी महत्व दिया गया।

वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था पुनः समग्र, दक्षतामूलक एवं बाल-केंद्रित मूल्यांकन की ओर अग्रसर हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन को केवल परीक्षा की प्रक्रिया न मानकर अधिगम सुधार का माध्यम माना गया है। इस नीति में दक्षतामूलक अधिगम (Competency-Based Learning), अनुभवात्मक शिक्षा (Experiential Learning), आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN), विद्यालय आधारित मूल्यांकन (School-Based Assessment) तथा समग्र प्रगति पत्र (Holistic Progress Card) जैसी अवधारणाओं को विशेष महत्व दिया गया है।

इसी संदर्भ में विद्यालय आधारित मूल्यांकन की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति का आकलन विद्यालय एवं कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों में निरंतर रूप से करते हैं। इसमें केवल लिखित परीक्षा ही नहीं, बल्कि कक्षा सहभागिता, परियोजना कार्य, गतिविधि आधारित अधिगम, मौखिक प्रस्तुति आदि में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी के सतत अवलोकन, सहपाठी मूल्यांकन तथा स्वमूल्यांकन को भी महत्व दिया जाता है। यह प्रणाली विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं, अधिगम की गति तथा बहुआयामी प्रतिभाओं को समझने में सहायक होती है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य केवल अंक प्रदान करना नहीं, बल्कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा प्रत्येक बालक के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। यह मूल्यांकन को भयमुक्त, बाल-अनुकूल एवं विकासोन्मुख बनाता है।

वर्तमान समय में मूल्यांकन को केवल परीक्षा की प्रक्रिया न मानकर “गुणवत्तापूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने की सतत एवं रचनात्मक प्रक्रिया” के रूप में देखा जा रहा है, जो शिक्षा के अन्य दो स्तंभों—पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्र-को दिशा प्रदान करती है। भारत की बदलती शिक्षा नीतियाँ इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं कि भविष्य की शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को परखना नहीं, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है।

विशेष रूप से विद्यालय आधारित मूल्यांकन की अवधारणा कहीं-न-कहीं उस प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण की ओर लौटने का प्रयास है, जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत क्षमता, अधिगम गति, व्यवहारिक कौशल तथा जीवन मूल्यों को महत्व दिया जाता था। आज पुनः शिक्षा व्यवस्था इस तथ्य को स्वीकार कर रही है कि प्रत्येक बालक अद्वितीय है तथा विशिष्ट प्रतिभा से युक्त है। इसलिए उसका मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वर्तमान शिक्षा व्यवस्था आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं प्राचीन भारतीय समग्र शिक्षा दर्शन के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अंतर केवल इतना है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में वैज्ञानिक मूल्यांकन तकनीकों, मानकीकरण तथा डिजिटल साधनों का समावेश अनिवार्य हो गया है।

यद्यपि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था समग्र एवं गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन की दिशा में अग्रसर है, फिर भी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। आज भी अधिकांश विद्यालयों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक एवं रैंक को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण विद्यार्थियों में परीक्षा तनाव, मानसिक दबाव तथा प्रतिस्पर्धात्मक अवसाद बढ़ता जा रहा है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना एवं उसके सफल क्रियान्वयन पर ही इसकी सफलता निर्भर करती है। इसके लिए व्यापक स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षकों पर अत्यधिक कार्यभार, बड़ी कक्षाएँ तथा संसाधनों की कमी भी प्रभावी मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न कर रही है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), डिजिटल मूल्यांकन, ऑनलाइन परीक्षण तथा डेटा आधारित अधिगम विश्लेषण जैसी नई प्रवृत्तियाँ तेजी से विकसित हो रही हैं। इन आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग तभी संभव है जब शिक्षकों को तकनीकी दक्षता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन क्षमता, रचनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमता तथा जीवन कौशलों के विकास पर बल दे रही है, जो भविष्य की शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

अतः यह स्पष्ट होता है कि भारत में मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास व्यवहारिक ज्ञान एवं व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित गुरुकुल प्रणाली से प्रारंभ होकर ब्रिटिशकालीन परीक्षा-केंद्रित व्यवस्था तक पहुँचा और वर्तमान समय में पुनः समग्र, बाल-केंद्रित एवं दक्षतामूलक शिक्षा की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आज की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली कहीं-न-कहीं प्राचीन भारतीय शिक्षा दर्शन की उस अवधारणा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसमें प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत क्षमता, व्यवहारिक दक्षता एवं सर्वांगीण विकास को महत्व दिया जाता था। वर्तमान शिक्षा नीतियाँ इस तथ्य को स्वीकार करती हैं कि मूल्यांकन का वास्तविक उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को अंक प्रदान करना नहीं, बल्कि उनके अधिगम, कौशल, व्यवहार एवं व्यक्तित्व विकास को समझना तथा उन्हें बेहतर सीखने की दिशा में अग्रसर करना है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। *सीखने के विश्लेषण के लिए संरचित मूल्यांकन (SAFAL)*। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2020)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*। भारत सरकार।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2022)। *राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) 2021: राष्ट्रीय रिपोर्ट*। भारत सरकार।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2023)। *दक्षता-आधारित मूल्यांकन का रोडमैप: PARAKH*, भारत सरकार।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2024)। *वार्षिक रिपोर्ट 2023-24*। भारत सरकार।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2005)। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*। एनसीईआरटी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2021)। *राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021: राष्ट्रीय रिपोर्ट* एनसीईआरटी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2023)। *स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*। एनसीईआरटी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2023)। *स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023: मूल्यांकन* एनसीईआरटी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2023)। *PARAKH: समग्र विकास के लिए ज्ञान के प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण का राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र* एनसीईआरटी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2024)। *राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021: तकनीकी रिपोर्ट* एनसीईआरटी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2024)। *समग्र प्रगति कार्ड: आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य एवं माध्यमिक स्तर* एनसीईआरटी।

PARAKH। (2025)। *विद्यालयी शिक्षा बोर्डों की समकक्षता के लिए प्रश्नपत्रों का मानकीकरण* राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, एनसीईआरटी।

PARAKH। (2026)। *परीक्षा सुधारा* राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, एनसीईआरटी।

PARAKH। (2026)। *नीति से व्यवहार तक: परीक्षा सुधारों के क्रियान्वयन के लिए PARAKH का रोडमैप* राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, एनसीईआरटी।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.